SHRI N. E. BALARAM : Madam, when the hon. Minister was there in Trivandrum last week, he promised to give them 10,000 tones of rice. This is the letter from the Minister. I do not want to read the letter. He says : "He received 2,000 tonnes and there are about 1½ lakh people still in the relief camps. They have no right to the supply." Can you do something abolt it ? I think you have got a copy of this letter.

SHRI BALRAM JAKHAR : I explained to those people as to what had happened. They had some understanding earlier regarding other supplies. So it was adjusted with them. But I told them that when I go back, I will ask them not to adjust it at that time and do it that way.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRIMATI SUSHMA SWARAJ) : All right. The Calling Attention is over. Now we will take up the Citizenship (Amendment) Bill, 1992.

THE CITIZENSHIP (AMENDMENT) BILL, 1992

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB) : Madam Vice-Chairman, I beg to move :

> "That the Bill further to amend the Citizenship Act, 1955, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The Government proposes to amend Section 4(1) of the Citizenship Act, 1955. The Convention on Elimination of All Forms of Discrimination against Women was adopted by Resolution No. 34/1980 of the U.N. General Assembly on the 22nd January, 1980. India was the Chairman of the Working Group which had drafted the Convention. The Preamble of the Convention notes that the State Parties to the International Conventions on Human Rights have the obligation to censure equal rights of men and women to enjoy all economic, social, cultural, civil and political rights. The term "discrimination against women" has been defined to mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has effect on purpose of impairing or nullifying the recognition, enjoyment or exercise by women, irrespective of their marital status, on the basis of equality of men and women of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural, civil or any other field. The ratification of this Covention by the Government of India had, however, been held up due to a conflict between Article 9(2) of the Convention and Section 4(1) of the Indian Citizenship Act, 1955. Article 9(2) of the Convention reads : "States parties shall grant women equal rights with men with respect to the nationality of their children." This is in conflict with existing Section 4(1) of the Citizenship Act, 1955 which provides that "a person born outside India on or after the 26th January, 1950 shall be a citizen of India by descent, if his father is a citizen of India at the time of his birth." Ratification of the Convention would require an amendment of the Citizenship Act so as to grant women equal rights with men with respect to the nationality of children.

There will be no expenditure from the Consolidated Fund of India.

Accordingly, it is proposed to enact the Citizenship (Amendment) Bill, 1992. The proposed legislation which is by way of amendment to the Citizenship Act, 1955 seeks that in future a child born abroad may become an Indian citizen if either of his parents is an Indian citizen at the time of his birth and also to make necessary consequential amendments in the Act.

With these words, I commend the Citizenship (Amendment) Bill, 1992, as passed by Lok Sabha, for the consideration of the House.

The question was proposed.

श्रीमती सरला माहेश्वरी (पश्चिम बंगाल) माननीय उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं आभारी हूं जो आपने मुझे पहले बोलने का मौका दिया। उपसभाध्यक्ष महोदया, स्त्रियों के साथ वर्षों से चले आ रहे इस कानूनी अन्याय को समाप्त करने के लिए यह जो नागरिकता (संशोधन) विधेयक लाया गया है, यद्यपि यह विधेयक भी कानून की कसौटी पर इंसाफ की कसौटी पर

पूरी तरह से खरा नहीं उतरता, इसके बावजूद मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं। क्योंकि इस विधेयक के जरिए वर्षों से नागरिकता कानून में लिंग के नाम पर महिलाओं के साथ जो भेदभाव किया जा रहा था उसको दूर करने का जो थोड़ा बहुत भी प्रयास किया गया है, उसके लिए मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

उपसभाध्यक्ष महोदया, अगर हमारे संविधान को देखें तो जहां तक नागरिकता का सवाल है, हमारे संविधान में स्पष्ट निर्देश हैं कि लिंग के आधार पर नागरिकता में किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इस स्पष्ट निर्देश के बावजूद हमारे यहां इस तरह का यह कानून बना रहा। इन कानून का बने रहना इस बात की ओर इंगित करता है कि किस तरह हमारी सरकार और हमारे प्रशासन में आज भी लिंग संबंधी पूर्वाग्रह बने हुए हैं। यह हमारी सरकार के लुंज-पुंजपन को, हमारी नौकरशाही के लुंज-पुंजपन को ही दर्शाता है और अगर हम गहराई से देखें तो एक नहीं, इस तरह के अनेकानेक कानून हम को मिल जाएंगे मसलन अभिभावक का कानून, जमीन की मिल्कियत के संबंध में कानून, संपत्ति संबंधी कानून और विवाह और तलाक आदि कानूनों को आप देखें तो इनमें लिंग संबंधी पूर्वाग्रह हमें मिलते हैं और यह सिर्फ हमारे देश में ही नहीं हैं दुनियां के अनेक देशों में महिलाओं के साथ सिर्फ लिंग के आधार पर भेदभाव करने वाले कानून बने हुए हैं। इसीलिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के भेदभावों को दूर करने के लिए आवाजें उठीं और इन्हीं आवाजों का यह परिणाम निकला कि सन् 1980 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक कार्यदल तैयार किया और उस कार्यदल की अध्यक्षता हमारे ही देश ने की। उस कार्यदल ने सन् 1980 में यह घोषणा की कि लिंग के आधार पर महिलाओं के साथ किसी भी तरह का आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक भेदभाव न हो। इस घोषणा के जरिए विभिन्न राज्यों को यह संदेश दिया गया, यह निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने यहां ऐसे कानून बनाएं ताकि महिलाओं के साथ अगर लिंग के आधार पर भेदभाव बरता जा रहा हो तो उसको दूर किया जा सके।

उपसभाध्यक्ष महोदया, 1980 की यह घोषणा और आज 1992 है, पूरा एक युग बीत चुका है, लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि जिस कार्यदल का अध्यक्ष स्वयं हमारा देश था, उस देश में 12 वर्षों के बाद यह कानून लाया जा रहा है। उपसभाध्यक्ष महोदया, अगर आप इस कानून को भी देखें, इस संशोधन को भी देखें तो इस संशोधन में नागरिकता के संबंध में दो श्रेणियां बनायी गयी हैं। एक श्रेणी 1950 के बाद और इस संशोधन कानून के पहले की है और दूसरी इस संशोधन कानून के बाद की है। तो जो पहली श्रेणी मंत्री महोदय ने निर्देशित की है, उस श्रेणी के अनुसार 1950 के बाद और इस संशोधन कानून के पहले तक अगर कोई बच्चा विदेश में जन्मा हो तो उसे भारतीय नागरिकता तभी मिल सकती है जबकि उसके पिता भारत के नागरिक हों। उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं यह जानना चाहती हूं कि हमारे मंत्री महोदय से कि आखिरकार इस भेदभाव को क्यों बरकरार रखा गया है? इसका क्या कारण है और उन महिलाओं ने कौनसा अपराध किया है कि 1950 के बाद से और इस संशोधन के बनने से पहले जो महिलाएं हमारे हिन्दुस्तान में रह रहीं थीं, वह आज भी इस संशोधन के बावजूद अपने बच्चों को भारत की नागरिकता नहीं दिला पाएंगी। हालांकि मंत्री महोदय, तर्क दे सकते हैं कि यह हमारे लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा। हमें पुराने केस खोलने पड़ेंगे, लेकिन उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं यह जानना चाहती हूं कि इतनी बड़ी मानवीय त्रासदी इसके पीछे छिपी हुई है, अगर उस त्रासदी को हम नहीं समझेंगे और केवल नौकरशाही पर पड़ने वाले काम के बोझ को देखेंगे तो क्या यह बड़ा

अन्याय नहीं होगा ? मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि इसकी क्या वजह है ? अगर यही वजह है तो कृपया इसे दूर कीजिए ताकि हम एक अन्याय को दूर कर सकें और साथ ही साथ दूसरे अन्याय का रास्ता हम नहीं बना रहने दें और फिर आने वाले 10 वर्षों के बाद हमें फिर संशोधन न लाना पड़े। तो ऐसी जरुरत न हो, इसलिए मैं चाहूंगी कि मंत्री महोदय इस पर कृपया ध्यान दें।

उपसभाध्यक्ष महोदया, इससे जुड़ा हुआ दूसरा एक अहम सवाल है, मैं उसकी तरफ भी मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। हाल ही में जो अनिवासी हैं, उन अनिवासियों को नागरिकता देने का सवाल किसी भी देश के राजनीतिक, आर्थिक विकास के साथ जुड़ गया है।

[उपसभाध्यक्ष (श्री एच० हनुमनतप्पा) पीठासीन हुए]

विज्ञान ने दुनियां को बहुत छोटा बना दिया है। मानवता को एक दूसरे के करीब ला दिया है, लेकिन विज्ञान ने जहां मानवता को एक दूसरे के करीब लाया है, वहीं पूंजीवाद ने मानवता को संकीर्ण भी बना दिया है, इसे छोटा भी कर दिया है। पूंजीवाद के साथ राष्ट्रवाद का जो अनिवार्य अंग जुड़ा हुआ है, उस राष्ट्रवाद के चलते अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आर्थिक स्वार्थ बहुत बड़ी भूमिका अदा करने लगे हैं और इसके चलते, उपसभाध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि वह पूंजीवादी राष्ट्र विशेषकर अमरीका, जो हमें मुक्त व्यापार और मुक्त वाणिज्य के बड़े बड़े उपदेश पिलाता रहता है वह स्वयं खुद कितना संरक्षणवादी है ? अमरीका की सुपर 301 की धमकी से भुक्तभोगी हमारे देश के लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं जिस बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं वह यह है कि लम्बे अरसे से जो यूरोपीय महासंघ की बात उठाई जाती रही है, लेकिन आर्थिक स्वार्थों की वजह से उनका यूरोपीय महासंघ का सपना भी साकार नहीं हो पा रहा है। यह पश्चिमी पूंजीवादी देश और यह तथाकथित सभ्य देश उस तरह आर्थिक स्वार्थों की आड़ में अपने नागरिकता कानूनों को भी ज्यादा से ज्यादा संकीर्ण बना रहे हैं और इस पश्चिमी सभ्यता को देखकर ही गुरू रवीन्द्र नाथ ने कहा था, मैं उनको उद्धृत करना चाहूंगी —"पाश्चात्य जातियों को अपनी सभ्यता पर जो गर्व है उसके प्रति श्रद्धा रखना अब असह्य हो गया है। यह सभ्यता हमें अपना शक्ति रूप दिखा चुकी है, लेकिन मुक्ति रूप नहीं दिखा सकी। मनुष्य का मनुष्य के साथ वह संबंध, जो सबसे अधिक मूल्यवान है और जिसे वास्तव में सभ्यता कहा जाता है, यहां नहीं मिलता"।

उपसभाध्यक्ष महोदय, रवीन्द्र नाथ जी की इस उक्ति के बाद एक लंबा काल गुजर चुका है, गंगा से बहुत सा पानी बह चुका है और इस काल में इन पश्चिमी राष्ट्रों का स्वार्थवादी रूप और भी निष्ठुर होकर हमारे सामने आया है। आज जो अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य संहिता तैयार करने के नाम पर "गेट वार्ता" चल रही है, उस "गेट वार्ता" के जरिए किस तरह विकासशील देशों को गुलाम बनाने का रास्ता प्रशस्त किया जा रहा है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी एक विश्व की पृष्ठभूमि में जो आर्थिक स्वार्थों के चलते, संरक्षणवाद के चलते, अपने नागरिकता कानूनों को लेकर संघर्ष करती जा रही है, ऐसे विश्व की पृष्ठभूमि में हमें अपने नागरिकता कानूनों को देखना होगा और आज की जरूरत को देखते हुए हमारे नागरिकता कानूनों को और भी उदार बनाना होगा।

आज जो अनिवासी बार-बार नागरिकता का सवाल उठा रहे हैं, हजारों हजारों अर्जियां सरकार के पास जमा पड़ी हैं, मैं चाहूंगी कि सरकार उन अनिवासियों को नागरिकता देने के बारे में उदारता के साथ सोचे ताकि हम उनकी आर्थिक और मानसिक तमाम शक्तियों का उपयोग अपने देश के विकास में लगा सकें। इसलिए यह बहुत जरुरी है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, इसी के साथ ही मैं यह कहना चाहूंगी कि इस नागरिकता कानून में जो संशोधन किया गया है, उस संशोधन में जो केटेगरी रखी गई हैं, जो श्रेणियां रखी गई हैं, उन श्रेणियों पर मंत्री महोदय फिर से पुनर्विचार करें और आज की जरूरत को देखते हुए हमारे नागरिकता कानूनों को उदार बनाने की जरुरत को समझें । आज हमारे अनिवासियों को नागरिकता देने की जरूरत है ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं और मंत्री महोदय से यह अपील करती हूं कि अगर हो सके तो वे इन श्रेणियों को समाप्त करने के बारे में सोचें । धन्यवाद ।

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry) : Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity to speek on the Citizenship (Amendment) Bill, 1992. Sir, I support this Bill. This Bill has been brought with a limited purpose—recognising the citizenship of a person born outside India to an Indian parent. In another amendment there is discrimination based on sex. Only male person has been recognised. Now it has been amended to any person. In Pondicherry we were ruled by the French. Mr. Minister kindly listen to me. I am talking about the dual citizenship. We were ruled by the French. In 1954, we got liberated. There was an agreement signed between the French Government and the India Government when the French people left India. Therefore there is a clear case of dual citizenship. The persons born in India, adopted the French citizenship. went to France or any of its colonies. They served there either in the executive side or in the army. And after retirement, they came back to India and got settled here. Now these persons who were born as Indians but were converted into French nationalities for the sake of employment and those people having got the jobs there, lived there for more than 20 years and have come to their home town, Pondicherry, are required to get permission from the French Consulate and also our Indian Government for their stay in India. These people, after their retirment, come to India to get permanently settled here. Several times they need to write to the Government and then they get the permision for their stay in India. I have raised this issue several times and I have also put a question in Parliament. I received a favourable reply from the Home Minister stating that the dual citizenship for the people who had adopted the French nationality and then returned to India would be considered. But there has been no formal announcement by the Government of India though it was agreed in principle. More than 5,000 to 6,000 people went to Franch or its colonies and they returned to India after their retirement. They are contributing a lot of money in foreign exchange to our Indian territory. Why I am saying this is that as pension, each pensioner gets a minimum of Rs. 10,000 to Rs. 30,000 per month in terms of our Indian currency. Thus by way of pension, these people are contributing a lot of foreign exchange. This dual citizenship should be allowed so that they could retain their Indian citizenship also and the anomaly of these people to apply and get permission every now and then from the French Embassy and also from our Government can be removed. This is a very vital issue. I would like the hon. Minister to consider this and accept this. The same problem is there in Goa also.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA) : Mr. Fernandes is speaking on this.

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa): Let him speak. I have no objection.

SHRI V. NARAYANASAMY : This is the common problem of all the Union Territories. As per the agreement signed between these two countries, this has been done. The citizenship problem is a never-ending problem in Pondicherry. I would like to give a very concrete example regarding registration of births. I visited some of the States. In some areas, they have got a foolproof system for the registration of births. Under the French system, there is a person called the 'Mayor'. 'Mayor' is a person who has got even the police powers under

the French system. The registration of births, maintenance of all civic amenities, registration of deaths, everything is done by him. And they have got a system by which the birth of a child has to be registered within seven days of the birth. The birth is registered there in what they call 'Marie', that is, the municipal corporation office. If they fail to register within this period they can register it within three months by getting a court order. Under the French system we call it 'Etat Civil,' the registration office. This was followed from 1910 till 1973 when we had changed the system according to our new system. Till 1973, the French Government had been maintaining the records about the births and deaths. They have got a family identity card that is given to each family in which mother's name, child's name, date of birth, etc., are given. The birth entry is the main thing for obtaining citizenship and this is not being maintained properly.

What are they doing ? They go through the school records. They go through the other records to find out the date of birth of a person to consider whether he is an Indian citizen or not. But in our earlier French system, it was a very perfect system by which the birth records had been maintained. That may also have to be considered. Now I come to the question of migration though it is irrelevant for this purpose. The migration question is daunting our country as far as the North-Eastern region is concerned. So many times, we raised this issue in the House. Today we have seen that the Bangladesh Government refused to accept the citizens of Bangladesh who entered into our Indian territory in spite of the negotiations which are going on. Then what is their status ? They are neither Indian citizens nor Bangladesh citizens. They are living in India. What are you going to say about them ? Are you going to repatriate them or are you going to give them citizenship ? In Assam, the burning isues of citizenship has now become a political issue. Therefore, I would like to know what the Government of India is going to do for them.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA) : Please conclude.

SHRI V. NARAYANASAMY : I will conclude with this final point. The hon. Minister has said that 26th January is the deadline. On or before 26th January, 1950 and before the commencement of this Act, if the father was an Indian citizen, even if a person was born outside India, he can be an Indian citizen. Why are you fixing the time-limit? Why 'on or before 26th January, 1950'? if the father of the person is an Indian citizen and he was born outside India, he is to be considered as an Indian citizen. Now there is another anamoly. If a foreigner marries an Indian women, they can get Indian citizenship and if an Indian women marries a foreigner, she is not recognised. This anamoly is also there. For a women, it is not there. Even today, it is not there.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA) : After this amendment, it will be there.

SHRI AJIT P. K. JOGI : (Madhya Pradesh) : After this amendment, it will be there.

SHRI V. NARAYANASAMY : I am coming to that. Let the hon. Minister reply to me to these points. Here for a foregner your are accepting. But for an Indian woman, you are ignoring this. Now, the hon. Minister has to satisfy us.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA) : He will satisfy in his reply.

SHRI V. NARAYANASAMY : Finally, between India and Pakistan, citizenship problems are there. Hindus are living in Pakistan and Muslims are living in India. Their kith and kin are living here and there. Neither can they come to India or can these people go there. What is their position ? Parents are living.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA) : That is not a citizenship issue.

SHRI V. NARAYANASAMY : Now the father is living here; the son is there and he would like to come to India. What will be his position ? The hon. Minister will have to reply. If the son wants to settle here and if the father is living here, irrespective of the religion

to which they may being, they should be allowed Indian citizenship.

Thank your Sir.

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे (गुजरात) : उपसभाध्यक्ष महोदय, सरकार की ओर से यह जो नागरिकता (संशोधन) विधेयक 1992 लाया गया है, उसका मैं स्वागत करता हूं । चुंकि जो बिल अमेंडमेंट है, बड़ा छोटा है । "एनी मेल पर्सन" की जगह पर "एनी पर्सन" का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है । लिंग के आधार पर नागरिकता का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, यह भी मैं मानता हूं कि यह नहीं होना चाहिए । लेकिन इस बिल में दो तीन बातें ऐसी हैं कि कहीं पर उसका दुरूपयोग नहीं होना चाहिए । मान लीजिए कि इस बिल का जो दुरुपयोग होगा वह हम सब जानते हैं कि हमारी देश की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है करोड़ों लोग घुसपैठ के माध्यम से हमारे देश में आ गए हैं । इस बिल के आधार पर यदि वे नागरिकता ले लेंगे तो हमारी क्या हालत होगी, यह मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं । लाखों लोग आ गए हैं । हमने कइयों को निकाला भी है यहां से लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद कई ऐसे लोग घुसपैठ के माध्यम से, जो बंगला देश से आ गए हैं, पाकिस्तान से आ गए हैं, आप हमारे इलाके कच्छ में आए थे, वहां से लाखों लोग आते हैं और वहां बैठे हैं और इस कानून के आधार पर वे हमारे सिटीजन बन जाएं तो क्या हालत होगी, मैं इसकी ओर आपका ध्यान खीचना चाहता हूं ।

मैं इस अमेंडमेंट का कोई विरोध नहीं कर रहा हूं, यह आना चाहिए लेकिन यहां से घुसपैठ की जो प्रवृत्ति चल रही है सारे देश में और हमारी आबादी उसकी वजह से बढ़ गई है, उसकी ओर हमारा ध्यान रहना चाहिए, इतना मेरा नम्र अनुरोध है ।

दूसरी बात जो आपने टाईम की बताई है, थ्रन इयर का टाईम दिया है, वह टाईम कुछ कम है । उसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है ।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के दबाव के कारण तो हम यह काम नहीं कर रहे हैं, अपनी इच्छा के अनुसार कर रहे हैं, तो भी ये हमें पहले करना चाहिए था लेकिन नहीं किया । अब हमने इसका अमेंडमेंट किया है तो जब हम इसका इंप्लीमेंटेशन करेंगे तो इसको इंप्लीमेंट करने के लिए कोई रुल्स बनेंगे, कोई नियम बनेंगे, तो उस पर हमारी सरकार का पूरा ध्यान रहे । ऐसे रुल्स न बन जाएं कि जिनके वजह से किसी गलत आदमी को सिटीजनशिप मिल जाए क्योंकि यह बड़ा गंभीर मामला है और इस पर अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे, इसके इंप्लीमेंटेशन में अगर गड़बड़ी हो जाएगी तो हमारे सामने तो एक समस्या पहले ही खड़ी है, दूसरी समस्या दिन-प्रतिदिन खड़ी होती जा रही है ।

मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और जो दो तीन दिन बातें आपको बताई है रुल्स बनाते वक्त सरकार उन पर ध्यान दे घुसपैठ के संबंध में भी ध्यान दे, ऐसी मेरी विनती है । इस बिल का मैं और मेरी पार्टी पूर्णतया समर्थन करते हैं।

श्री मूल चन्द मीणा (राजस्थान) : उपसभाध्यक्ष महोदय, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल का तो मैं समर्थन करता हूं । आज इस बिल को लाकर मंत्री जी ने मानवता में जो एक भेद था, उस भेद को मिटाने का प्रयास किया है । अब से पहले लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष में जो भेद था नागरिकता प्राप्त करने के संबंध में, उसको दूर करने के लिए यह बिल लाया गया है । यह अच्छी भावना के साथ लाया गया है, इस देश की स्त्रियों को सम्मान देने के लिए यह बिल लाया गया है और जब जब इस देश में नारियों का सम्मान हुआ है, तब-तब इस देश की उन्नति हुई है। पता नहीं क्यों अब तक यह भेद चला आया था कि पुरुष इस देश का रहने

वाला है और विदेश में रहता है तो उसके बच्चे को तो यहां की नागरिकता प्राप्त हो जाती थी लेकिन इस देश की स्त्री यदि विदेश के अन्दर रहे, उसके बच्चे हों तो उनको यहां की नागरिकता प्राप्त नहीं होती थी। यह एक गलत बात थी। जिसको आज संशोधन के माध्यम से ठीक किया जा रहा है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं लेकिन साथ ही मैं मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। इस देश के अंदर अंग्रेजों का राज रहा, फ्रांसीसियों का राज रहा। कई गड़बड़ियां इस नागरिकता के संबंध में हुई। कई लोग दूसरे देशों में सत्ता के साथ इस देश को छोड़ कर चले गए, चाहे वह सेना के अंदर गये हों, चाहे सरकारी नौकरियों के अंदर विदेशों में जाकर काम किया हो। जो लोग यहां से चले गये उनकी स्त्रियां, उनकी लड़कियां जो भारत की नागरिक थीं उनको जो अधिकार इससे मिल रहा है वह कहीं वंचित न रह जाए इसका ध्यान रखा जाए। इस देश के अंदर जो घुसपैठ हुआ चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे बंगला देश का हो, असम के अंदर आज उसी के कारण समस्या बनी हुई है, इस पर विशेष गौर करने की आवश्यकता है। यहां इसको लागू करते समय कुछ ऐसे लोग जो फर्जी रूप से प्रमाणपत्र ले आएं स्त्रियों के नाम से ले आयें, इस पर विशेष निगाह रखने की बात है। कहीं ऐसा न हो कि इस बिल की भावना अच्छी बनते-बनते, स्त्रियों का सम्मान करते-करते, इसका दुरूपयोग हो जाए। साथ ही आप यह जो बिल लाये हैं इसका हम स्वागत करते हैं। जयहिन्द।

श्री रामदेव भंडारी (बिहार) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आपके सौजन्य से मुझे पहली बार इस सर्वोच्च सदन में खड़े होकर अपनी बात कहने का अवसर मिला है। मैं सिटीजन अमेंडमेंट बिल 1992 का समर्थन और स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बिल बहुत पहले आना चाहिए था। मंत्री महोदय ने इसे सदन में लाने में काफी विलम्ब किया। फिर भी देर आए दुरूस्त आए। यह मानकर इस बिल को हम स्वागत योग्य समझते हैं।

यह भारतीय समाज एक पुरुष प्रधान समाज है और इस समाज में, भारतीय संविधान में, हम स्त्रियों को सम्मानित करने और बराबर का दर्जा देने की बात तो करते हैं मगर व्यवहार में ऐसा नहीं होता। कहने के लिए तो हम कहते हैं कि नारी गृहलक्ष्मी है, मगर इस देश के अंदर जब नारी होश संभालती है गृहदासी के रूप में काम करना शुरू करती है और मरते दम तक गृहदासी ही बनी रहती है।

इस संबंध से जब हम देश और विदेश में नारी मुक्ति आंदोलन की बात करते हैं, करने की चर्चा करते हैं तो इस अवसर पर इस बिल को लाकर मंत्री जी ने एक स्वागत योग्य कदम उठाया है। इस भारतीय समाज में बच्चे के प्रति, सन्तान के प्रति जो मां की भावना होती है, मां का कर्तव्य होता है वह बाप से कहीं अधिक ज्यादा, कहीं अधिक विशाल होता है। किसी ने कहा भी है :

"Fatherhood is a presumption and the motherhood is a certainty."

नाम तो मां का चलना चाहिए क्योंकि यह देश पुरुष प्रधान देश है इसलिए बाप का चलता है। हम स्कूल में, कालिज में कहीं भी जाते हैं तो अपने लड़के या लड़की के नाम के साथ बाप का नाम जोड़ते हैं। मैं सुझाव दूंगा कि अगर सिर्फ मां का नाम न जोड़ा जाए तो कम से कम बाप के नाम के साथ मां का नाम जरूर जोड़ा जाए।

यदि हम स्कूल में और कालेज में कहीं भी अपने बच्चों का नाम लिखाने जाते हैं तो दोनों का नाम साथ-साथ लिखा जाए।

महोदय, हमारे समाज के जो बच्चे विदेशों में पैदा होते हैं वे हमारे ही बच्चे होते हैं। चाहे बाप के साथ उनका नाम जुड़े या मां के साथ नाम जुड़े, वे हमारे अपने बच्चे हैं और उन्हें इस

देश की नागरिकता प्राप्त करने में किसी तरह की कोई कठिनाई न हो इसके लिए इस बिल ने बहुत बड़ा काम किया है। मैं मंत्री महोदय से सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा उपसभाध्यक्ष जी के माध्यम से कि आप देखें कि इस बिल का किसी भी स्थिति में दुरुपयोग न हो। कई सदस्यों ने कहा कि भारत में इस समय हजारों की संख्या में लाखों की संख्या में दूसरे देशों के लोग आते हैं और कई तरह से और कई प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और कभी कभी गलत ढंग से फर्जी नागरिकता प्राप्त कर भारत को नुकसान भी करते हैं। ऐसी स्थिति में हमें सावधान रहना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा कि जो सच्चे मन से, ईमानदारी से, इस देश की नागरिकता प्राप्त करेंगे, इस देश के नागरिक बन कर इस देश की सेवा करेंगे, उन्हें हम निश्चित रूप से नागरिकता देंगे जिससे वे इस देश की सेवा कर सकें।

इन्हीं शब्दों के साथ मंत्री जी का जो यह बिल है इसका मैं समर्थन करता हूं और उपसभाध्यक्ष जी, एक बार पुनः आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस बड़े सदन में मुझे बोलने का अवसर दिया।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA) : Shri Ish Dutt Yadav, not here. Dr. Thulasi Reddy.

DR. NARREDDY THULASI REDDY (Andhra Pradesh) : Sir, it seems the Government has some starting trouble. Sir, the General Assembly of the United Nations adopted Resolution No. 34/1980 on 22-1-80 regarding elimination of discrimination against women, which includes discrimination against nationality also. That was in 1980. India was the Chairman of the Working Group which drafted the Resolution. Now it is 1992, that is, after 12 years, that is after one Pushkaram, the Government remembered the Resolution and it is trying to implement it. Anyhow, better late than never.

Sir, in our Constitution, articles 14, 15 and 16 say that there should not be any discrimination on the basis of sex. But I wonder why this anomaly of discrimination against women has found a place in the Citizenship Act of 1955. As per this Act, a child born abroad would become a citizen of India if the child's father was a citizen of India at the time of the child's birth. In the present amendment Bill, this anomaly has been re-removed and a child born abroad would become a citizen of India if either of its parents is a citizen of India at the time of that child's birth. This is a welcome feature. In this non-discrimination Bill, again there is a discrimination. A child born after 26-1-50 and before the commencement of the amended Act, he would become citizen of India if its father is a citizen of India at the time of the child's birth. The child born on or after commencement of this amended Act would become citizen of India if either of the parents is a citizen of India at the time of the child's birth. Therefore, in this Bill, which wants to do away with discrimination, there is again discrimination. I am not able to understand why this should not be implemented with retrospective effect. Why can't it be implemented with retrospective effect ?

Then, there are some other laws also where there is discrimination against women. For example, the guardianship law. If the child is to be admitted in a school, against the column 'guardian', we say 'father'. All of us know that 'father' is presumption and 'mother' is certain. Therefore, in my opinion, it is better to put 'mother' as guardian than 'father'. This guardianship laws should also be amended.

Then, I come to the question of dual citizenship. A number of advanced countries have this dual citizenship. Since most of the NRIs are in a well-to-do position, they can contribute in a big way, in the form of resources, in the form of knowledge, in the form of technology. Therefore, it would be beneficial to our country if we give dual citizenship to the NRIs.

I hope the hon. Minister would clarify these points. With these observations, I support this Bill.

SHRI JAGMOHAN (Nominated) : Mr. Vice-Chairman, Sir, I have three-four points to make.

One is, I support the Bill.

Secondly, I do not understand why retrospective effect cannot be given to it. If Government thinks that the number of cases would be too large, it can have an enabling provision in the Act, under which it can, in exceptional cases of hardship, give relief and give citizenship right even retrospectively. It should have the powers and if there is a case meriting consideration, it can grant the citizenship right. The discretion should be with the Government; in other cases, the legislation can take effect from the date it is notified.

My third point is, there are a large number of women in Jammu and Kashmir. They are being discriminated against in a very wrong way. For instance, even if she has her citizenship right in the State and she is also a citizen of India, the moment she marries a person outside Jammu and Kashmir, she losses her rights which she earlier enjoyed. She loses her rights within the State. This is a discrimination. Now that you have President's rule in the state, please set right this discrimination.

The fourth point is there are 12-13,000 families who came to Jammu and Kashmir, which is a part of India in 1947, due to riots and other compuisions. They did not come for a holiday or anything of that sort. They came because of the compulsions of circumstances. They, their children and grand children, have been denied citizenship rights for the last forty-five years. They cannat vote in the Assembly elections. They cannot vote in panchayat elections. They cannot become members of co-operative societies. They cannot get even loans under the twenty-point programme. They cannot get admission in the engineering, agricultural and medical colleges, even when all these colleges are set up with hundred per cent finances made available by the Union of India. When this matter was taken by some persons to the Supreme Court, the Supreme Court recognised the injustice that was being done to these people. In their judgement of 25th February, 1987, the Supreme Court had suggested that this injustice done to these people should be rectified by some amendments such as amendments to the Panchayat Act and other Acts. The court could not give any relief to them because of article 370 - the State's special status - and the Constitution of Jammu and Kashmir. The Court said that this was a very antiquated and there was injustice. At the same time, the court had also suggested the way out. For example, if any one is not getting jobs, executive instructions could be issued. The Kashmir Civil Service Rules could be amended. This can be done by the State Government. The co-operative laws can be amended. Without amending article 370, without amending the Constitution of the State, you can do justice to these people. We have been fighting for the citizenship, for the human rights of the Palestinians, South Africans, and we are committed to the rational of the human rights. That in our own country people should be denied these elementary rights for the last 40 to 45 years is not understandable. These are the four submissions which I have to make and I would request the Government to kindly consider whether they can bring forward a separate legislation or they can take other measures, whichever they may consider appropriate, to rectify the unjust situation.

श्री अजीत जोगी : उपसभाध्यक्ष जी, नागरिकता संशोधन विधेयक 1992 का मैं स्वागत करता हूं । भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की संविधान सभा में जो फैसला

किया गया था उसके हस्ताक्षरकर्त्ताओं में से था और उसमें जो सार्वजनिक रूप से सभी राष्ट्रों के बीच सहमति हुई थी उसके अनुसार इस संशोधन को प्रस्तुत किया गया है। संशोधन अच्छा है और सदन के सभी लोगों ने पार्टी की सीमाओं से ऊपर उठकर इसका स्वागत किया है। मैं भी करता हूं।

मैं आपके माध्यम से एक निवेदन मंत्री महोदय से करना चाहूंगा। नागरिकता के संबंध में एक भ्रांति, एक कमी अभी भी रह गयी है। बहुत से ऐसे राष्ट्र हैं जहां नागरिकता के संबंध में यह नियम है कि व्यक्ति कहीं का भी हो यदि उसका जन्म उनकी भूमि पर होता है तो वह व्यक्ति वहां का नागरिक हो जाता है जैसे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है। वहां यदि किसी भारतीय मां के द्वारा कोई पुत्र उत्पन्न होता है तो वह अपने आप अमेरिका का नागरिक बन जाता है। इस कानून और इस संशोधन के अनुसार चूंकि उसकी मां और उसके पिता भारत के हैं इसलिए वह भारतीय नागरिक भी बन गया। इस तरह से वह व्यक्ति एक ही समय में उस राष्ट्र का भी जहां उसका जन्म हुआ था और इस संशोधन के अनुसार तथा हमारे वर्तमान कानून के अनुसार वह भारत का भी नागरिक है। दो राष्ट्रों की नागरिकता उसको प्राप्त हो जाती है। वर्तमान में हम अपने संविधान में अपने कानून में डुअल सिटीजनशिप, दो राष्ट्रों की नागरिकता को मान्यता नहीं देते हैं। ऐसी परिस्थिति में जबकि हम यह संशोधन ला रहे हैं अब हमें गम्भीरता से यह विचार करना पड़ेगा कि हमारे राष्ट्र में भी भारत में भी हम डुअल सिटीजनशिप के सिद्धांत को मान्य करें। मैं ऐसा इसलिए निवेदन कर रहा हूं क्योंकि पूर्व में बहुत से राष्ट्रों में हमको बड़े कटु अनुभव हुए हैं। हमारे भारतीय मूल के बहुत से लोग अफ्रीका में थे। अफ्रीका में उन्होंने अपने-आप को स्थापित किया। किन्तु उनकी निष्ठा, उनका प्रेम भारत के प्रति बना रहा। अफ्रीका में ऐसे बहुत से राष्ट्राध्यक्ष आये जिन्होंने उन लोगों को निकाल दिया। वे वहां के भी नहीं रहे और चूंकि इस कानून के अनुसार भारत के नागरिक भी नहीं बन सकते थे इसलिए भारत के नागरिक भी नहीं रहे। इसी तरह से अभी हम यह देख रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में जो आप्रवासी भारतीय हैं, एन०आर०आईज० हैं उन्होंने बहुत बड़ा योगदान किया है। एन०आर०आईज० आज दूसरे राष्ट्रों के नागरिक हैं, किन्तु उनकी निष्ठा, उनका प्रेम उनका संबंध उनका रिश्ता भारत से बना हुआ है। यदि हम एन०आर०आईज० को यह मौका दे सकें कि वे जिस राष्ट्र में जाकर बस गये हैं जहां कमा रहे हैं वहां के नागरिक तो रहें ही किन्तु साथ ही जिस राष्ट्र से उनका मौलिक संबंध है, मूल संबंध है अर्थात् भारत के भी नागरिक रहें तो उनका एक भावनात्मक संबंध इस राष्ट्र से और बन जाएगा तथा वे इस राष्ट्र के आर्थिक विकास में और योगदान दे सकेंगे। इस लिए मैं आपके माध्यम से ये दो निवेदन इस संशोधन का स्वागत करते हुए करना चाहूंगा एन०आर०आईज० के संबंध में कि जो भारत के लिए योगदान दे रहे हैं जिनकी भारत के लिए निष्ठा है जिनका भारत के प्रति प्रेम है जिनका भारत से लगाव है उनको हम डुअल सिटीजनशिप का आनर देकर, सम्मान देकर भारतीय नागरिक होने का भी लाभ उठाने दें जिससे भारत के प्रति और समर्पण से और बड़ी भावना से वे काम कर सकें। इसी तरह से ऐसे राष्ट्रों में, जहां केवल जन्म से ही नागरिकता प्राप्त होती है, वहां अगर कोई जन्म लेता है, पर उसके माता या पिता भारत मूल के हैं, तो उसे भी दोनों राष्ट्रों की नागरिकता बनाये रखने का अवसर दें।

यदि वह दो काम कर दिये जाते हैं, तो नागरिकता का जो कानून है, वह अपने आप में बहु-आयामी होगा और भारत के लिए लाभदायक होगा ।

धन्यवाद .... (व्यवधान) ....

SHRI JOHN F. FERNANDES : Sir, I rise to support the Citizenship (Amendment) Bill, 1992. Though there is no Statement of Objects and Reasons attached to this Bill, it is, obvious, after reading the Bill, that the intention of the Government is to remove the disparity between males and females. It is the intention of the Government, through this amendment, to see that the rights are given to children of a lady also of Indian origin.

Sir, though the Constitution gives equal rights through the Fundamental Rights, I think there was a lacuna in our Statute, and this is one Bill which will remove the lacuna. Therefore, I feel that this is a welcome step by the Government of India and this Bill will give equality in the real sense.

Sir, many countries offer dual citizenship to their citizens. For example, if you are a British national, you can also hold the nationality of Australia. I feel there are many people from the erstwhile colonies who are entitled to this, though not legally, as already mentioned by Mr. Narayanasamy—to which I will come later. But here I feel that the option should be given to the child, when the child attains the age of majority. When the age of majority is 18, when the child is entitled to vote in our country, I think it is not proper to force a citizenship on the child when the child is still a minor. Therefore, I feel that provision will be made by the Home Ministry to see that, though the mother may say that the child will be an Indian national, the real choice should lie with the child when he reaches the age of majority, that is, 18 years, when the child is entitled to vote in our country. I hope the Home Minister would make this provision also in this amendment.

Sir, ours is a multifaceted society. We have different ethnic groups with various customs and cultures. Though the society is patriarchal on this side of the country, if you go to the North-East you will find that the society there is matriarchal, that is, the mother is the head of the family. So I feel that there is a lacuna in our Statute that we have not decided whether we should give equality to man and woman, and I think this Bill will do away with that disparity.

Sir, my friend, Mr. Narayanasamy, has mentioned about the problem faced by his Union territory because Pondicherry was earlier a French colony. And in Goa, we have a very peculiar law. It is an unwritten law and it is not brought to the Government of India's notice. The pockets of Goa, Daman and Diu, when they were colonial pockets under the Portuguese Salazar regime, were taken over by force by the Government of India. So, the Portuguese Parliament, under the dictator Salazar, passed a law saying that the Union territory of Goa, Daman and Diu was not surrendered to the Government of India but was taken over by force and, so, any citizen who was born or whose parent was born in Goa prior to the liberation of Goa, that is, 19th December 1961, can opt for Portuguese nationality. This law is still in force and it is called *Sedula*. You go there and produce a birth certificate saying that you or your parent was born in Goa prior to the liberation of Goa, and you are entitled to a *Sedula*, that is, a Green Card. In this way, I think some of our nationals are holding dual citizenship. They are holding a Portuguese passport and an Indian passport also. So, I feel that the Home Ministy should take some steps to see that this agreement is legalised. I don't think that there is anything wrong in that because most of the people opt for

the Portuguese nationality to obtain the citizenship to work there. When they work there, they send money here. So, I don't think that they are going to sell their patriotism. So, it is a matter of compulsion for them to have some livelihood. Therefore, I feel that the Home Ministry should take up this matter with the Government of Portugal because that Government is not a dictatorial government, but it is a popular government.....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA) : Please conclude now.

SHRI JOHN F. FERNANDESE : .... and see that this system is legalised.

With these few words, I feel that the Home Minister's bringing this Bill is not very late because we have seen even in the most modern European countries—for example, in Switzerland—the women got their voting rights only in 1971. So, I don't think we are very late. Better late than never. I would request the hon. Home Minister to see that this law is made applicable with retrospective effect so that most of the citizens can avail of this facility.

With these few words, I support this Bill.

Thank you.

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल (उत्तर प्रदेश) : सदर सहाब, मैं समझता हूं कि जो बिल पेश किया गया है इस पर तो कोई बहस ही नहीं होनी चाहिए थी और इसको वैसे ही पास कर देना चाहिए था ।

उपसभाध्यक्ष (श्री एच० हनुमनतप्पा) : फिर आप भी बहस करना चाहते हैं ? .... **(व्यवधान)**

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल : मैं ताईद कर रहा हूं और उसका थोड़ा सा फायदा उठा रहा हूं .....। **(व्यवधान)** मैं, जो अजीत जोगी साहब ने मसला उठाया है उस तरफ तवज्जह होम मिनिस्टर साहब की दिलाऊंगा । गुजिश्ता दिनों मेरा लंदन जाने का इत्तफाक हुआ और वहां पर बहुत सारे वफद आ करके हमसे मिले थे। वहां मैंने यह महसूस किया कि हमारे जो हिन्दुस्तानी भाई वहां पर रहते हैं और जिनको वहां की सिटिजनशिप हासिल हो गई है उन लोगों में इस बात का बड़ा दर्द है कि वे हिन्दुस्तानी हैं, लेकिन उनके पास हिन्दुस्तान की शहरियत नहीं है । बहुत ज्यादा उनकी यह इच्छा है और मैं समझता हूं कि बड़ी जायज वे अपनी धरती से अपना रिश्ता जोड़े रखना चाहते हैं । तो मैं ज्यादा न कहते हुए यह कहूंगा कि उस पर हकूमत को बहुत संजीदगी से गौर करना चाहिए। उसके फवाहद भी हमारे जोगी सहाब ने बताए कि उससे हमको कोई नुकसान नहीं होने वाला है, उससे हमको फायदा होने वाला है । जो लोग हमारी धरती से जुड़े हुए हैं और आज गैर मुमालिक में जिनकी हालत बहुत अच्छी है वह अगर उनको हम यहां की सिटीजनशिप दें और ड्यूल सिटीजनशिप को मान लें तो उससे मुल्क को बड़ा अच्छा लाभ और फायदा हो सकता है, क्योंकि एक हद तक तो वे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे यहां आते हैं, जाते है, लेकिन एक स्टेज वह आती है जो साउथ अफ्रीका के अन्दर है और खुद अरब मुमालिक में भी मैंने ऐसे लोग देखे जो हिन्दुस्तान से गए थे । आज उनके घर में अरबी बोली जाती है और वे बिल्कुल अरबी हो गए हैं, उसके बावजूद वे हिन्दुस्तानी सीखते हैं । उनकी कई नस्लें वहां गुजर चुकी हैं और बेपनाह पैसे वाले हैं और

बहुत ज्यादा इन्वैस्ट कर सकते हैं। लेकिन सवाल वही है कि अगर उनको ड्यूल सिटीजनशिप दी जाए ? दूसरे मैं यह सिटीजनशिप के सवाल को उठाया गया एक तो मैं वजीरे दाखिला साहब की तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि सन् 1983 में बिहार के कुछ इलाकों में किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार में सिटीजनशिप के नाम पर और बगैर कुछ चैक किए बंगलादेशियों का एक सवाल उठाया गया था। काफी लोगों को उसमें पकड़ा गया और कोशिश की गई कि वहां भेजा जाएगा। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं भी उस वफद में शामिल था, उसमें तारिक अनवर साहब जो कांग्रेस के एक्स एम०पी० थे और जमीलुर्रहमान साहब थे। हम लोग जाकर मिसेज गांधी से मिले थे और हमने उनको बताया था कि इस तरह ज्यादती हो रही है गांवों और देहातों के अन्दर गरीब लोग, जो बिल्कुल कुछ जानते ही नहीं हैं उनसे एक वन फाइन मार्निंग आप कह करके कहें कि आप बंगलादेशी हैं तो वह कैसे प्रूफ करेगा। मैं वाईस चेयरमैन साहब, आपके वह 1983 में मिसेज गांधी ने जब इसको सुना तो उन्होंने इस पर संजीदगी से गौर किया और इसके बाद उन्होंने इस जो सब हरकत वहां की जा रही थी बिहार में उसको रुकवाया और अब फिर वही सिलसिला यहां दिल्ली में और बिहार में दोबारा से शुरू कर दिया गया है। तो मैं होम मिनिस्टर साहब की तवज्जह दिलाना चाहता हूं कि क्योंकि मैं दिल्ली में एक इलाका है सीमापुरी, खुद वहां पर गया हूं और जाकर मैंने अपनी आंखों से उन लोगों को देखा है। वहां बंगाली बोलने वाले कोई 35–40 हजार लोग रहते हैं और उनमें 99 परसेंट नहीं कहूंगा लेकिन 95 परसेंट मुसलमान हैं। वहां एक दिन सुबह को अखबार में खबर आई कि बंगलादेशी हैं ये लोग और इनको बार्डर पर छोड़ा जाएगा। 150 आदमियों को ट्रेन में भर करके और सारे अखबारों में उसकी फ्रंट पेज पर तस्वीर भी छपी है, ट्रेन में लोड करके उनको बंगाल के बार्डर पर ले जाया गया। फिर बंगाल के अखबारों में उसकी तस्वीरें छपीं कि बॉर्डर पर बिठाकर उन लोगों के सिर मूंडे गए, सिर साफ किए गए और उसके बाद उनको धकेलने का काम किया गया। धकेले जाने के बाद बंगला देश का जो फोर्स है वह गोली चलाता है। उसमें कुछ लोग मारे भी जाते हैं और कुछ लोगों को फिर वापिस भेज देता है और घूम-फिरकर वह लोग फिर वापिस आ जाते है। वहां जो डेढ़ सौ लोग भेजे गए थे, उनमें से कुछ वापिस भी आ गए फिर उसके बाद रातों मे वहां तकरीबन एक-दो हफ्ते तक बाकायदा जो हमारी जमुना पार की पुलिस है, वह रोज वहां पर जाती थी। मोहतरम् वाइस चेयरमैन साहब, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैंने खुद जाकर औरतों के इंटरव्यू लिए हैं और मेरा जो अखबार निकलता है, मैंने उसके अंदर उसको शाया किया है। लड़कियों को रेप किया गया और रात में जाकर उनको हरास किया गया कि यहां से भाग जाओ क्योंकि तुम बांग्लादेशी हो। वे रात में जाते थे, किसी भी झोंपड़ी से लड़की को उठा लिया और उसको ले जाकर दूसरे कमरे में रेप किया। उसमें एक औरत ऐसी थी कि उसकी बेटी को और उस औरत को दोनों को एक साथ रेप किया। उनके नाम और उनकी उम्र मैंने शाया की है। जब ये लोग उठाए गए वहां से तो किस तरह से उठाए गए,

वह मैं आपको बताना चाहता हूं। बाप को उठा लिया और जवान लड़के को उठा लिया। उसकी लड़कियों को और बच्चों को छोड़ दिया। इसी तरह एक फेमिली से दूसरे लोगों को उठा लिया बगैर कोई प्रूफ दिए।

श्री एम० एम० जैकब : सिटीजनशिप पर बोलिए।

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल : मैं सिटीजनशिप पर ही बोल रहा हूं साहब। यह मसला बहुत अहम है। आप इंसानियत के नाते सुनिए। मैं यह कह रहा हूं कि सरकार अगर किसी को उठाती है तो उसको यह साबित करना चाहिए कि तुम यहां के सिटीजन नहीं हो। दूसरे, अभी एक बयान आया। बहुत से लोग कहते हैं कि 5 लाख बांग्लादेशी हिन्दुस्तान में आ गए हैं। कोई कहता है कि 7 लाख हिंदुस्तानी बांग्लादेश के अंदर आ गए है। मेरा कहना यह है कि हो सकता है गुर्बत और लाचारी से तंग आकर बहुत से बांग्लादेशी आ गए हों और मैं यह भी मानता हूं कि बहुत सी जगहों पर वे मौजूद हों। तो सरकार को इस सिलसिले में, पूरी तवज्जो के साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि कहां-कहां बांग्लादेशी हैं यह मालूम करना चाहिए और उसका तरीका यह नहीं है कि आप रेलों में या बसों में लोगों को भरें और बॉर्डर पर धकेल दें। उसका तरीका यह है की आप बांग्लादेश की सरकार से बात कीजिए जिस तरह से कि बिहारियों के मसले पर पाकिस्तान से बांग्लादेश की बात चल रही है उसी तरह से आप बांग्लादेश से बात करें और उनकी सिटीजनशिप के मसले को तय करें कि वह यहां के हैं वहां के हैं। अगर वहां के हैं तो आप उनको वहां भेज दीजिए, लेकिन बांग्लादेशी के नाम पर और सिटीजनशिप का सबूत मांगने के नाम पर गरीब लोगों के साथ जुल्म और खास तौर पर एक कम्युनिटी को निशाना बनाया जाए, यह बहुत ही नाइंसाफी की बात है।

वजीरे दाखिला यहां बैठे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि दिल्ली में सीमापुरी में जो होता रहा है वे उसकी तहकीकात करें और यह मालूम करें कि क्या उनको यह साबित करके भेजा गया है कि ये लोग बांग्लादेशी हैं? क्या उनकी सिटीजनशिप के बारे में मालूम किया गया था? पिछले 15 साल से तीन-तीन इलेक्शंस में वह वोट दे चुके हैं। उनके पास राशन कार्ड्स हैं और सब कुछ है, उसके बावजूद यह जुल्म हो रहा है। जब वहां पर जाकर एतोजात किया तब पुलिस ने थोड़ी बहुत नरमी बरती वरना रोज वहां जाकर लड़कियों को रेप करने से लेकर दुनियां का हर काम वहां पर किया उनको हरास करने का।

इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और कहता हूं कि आप जो बिल लाए हैं वह बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंसानी बुनियाद पर तैयार किया गया है, लेकिन आपकी इंसानी हमदर्दी तमाम लोगों के लिए होनी चाहिए किसी मकसूस ताल्लुक से नहीं होनी चाहिए और सिटीजनशिप के जो तमाम मामलात हैं, उन पर पूरी तरह गौर करके सरकार को यह देखना चाहिए कि कहां-कहां नाइंसाफी हो रही है। बहुत-बहुत शुक्रिया।

ان کی یہ اچھا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑی جائز ہے کہ وہ اپنی دھرتی سے اپنا رشتہ جوڑے رکھنا چاہتے ہیں۔ تو میں زیادہ نہ کہتے ہوئے یہ کہوں گا کہ اس پر حکومت کو بہت سنجیدگی سے غور کرنا چاہیئے۔ اس کے فوائد بھی ہمارے جوگی صاحب نے بتائے کہ اس سے ہم کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے۔ اس سے ہم کو فائدہ ہونے والا ہے۔ جو لوگ ہماری دھرتی سے جڑے ہوئے ہیں اور آج غیر ممالک میں جن کی حالت بہت اچھی ہے وہ اگر ان کو ہم یہاں کی سٹیزن شپ دیں اور ڈبوں سٹیزن شپ کو مان لیں تو اس سے ملک کو بڑا اچھا لابھ اور فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ ایک حد تک تو وہ پیسہ انویسٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں آتے ہیں جاتے ہیں لیکن ایک اسٹیج وہ آتی ہے جو ساؤتھ افریقہ کے اندر ہے۔ اور خود عرب ممالک میں بھی میں نے ایسے لوگ دیکھے جو ہندوستان سے گئے تھے۔ آج اُن کے گھر میں عربی بولی جاتی ہے اور وہ بالکل عربی ہو گئے ہیں۔ اس کے

شری محمد افضل عرف م۔ افضل:
"اتر پردیش" صدر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ جو بل پیش کیا گیا ہے اس پر تو کوئی بحث ہی نہیں ہونی چاہیئے تھی اور اس کو ویسے ہی پاس کر دینا چاہیئے تھا۔

اُپ سبھا ادھیکش" شری ایچ ہنومن تھیا": پھر آپ بھی بحث کرنا چاہتے ہیں....." مداخلت"....

شری محمد افضل عرف م۔ افضل: میں تائید کر رہا ہوں اور اس کا تھوڑا سا فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ ....

" مداخلت" .... میں۔ جو اجیت جوگی صاحب نے مسئلہ اٹھایا ہے۔ اس طرف توجہ ہوم منسٹر صاحب کی دلانا چاہوں گا۔ گذشتہ دنوں میرا لندن جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں پر بہت سارے وفد آکر ملے تھے ہم سے۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے جو ہندوستانی بھائی رہتے ہیں وہاں پر اور ان کو وہاں کی سٹیزن شپ حاصل ہو گئی ہے۔ ان لوگوں میں اس بات کا بڑا درد ہے کہ وہ ہندوستانی ہیں لیکن اُن کے پاس ہندوستان کی شہریت نہیں ہے۔ بہت زیادہ

†[ ] Transliteration in Arabic Script.

ایک "ون فائن مارننگ" آپ کہہ کر سکتے کہیں کہ آپ بنگلہ دیشی ہیں تو وہ کیسے پرورکرے گا۔ میں وائس چیئرمین صاحب۔ آپ کے وہ ۱۹۸۳ء میں مسز گاندھی نے جب اس کو سنا تو انھوں نے اُس پر سنجیدگی سے غور کیا اور اس کے بعد انھوں نے جو سب حرکت وہاں کی جارہی تھی بہار میں اس کو رکوایا۔ اور پھر وہی سلسلہ یہاں دلّی میں اور بہار دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے۔ تو میں ہوم منسٹر صاحب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ کیونکہ دہلی میں ایک علاقہ ہے سیماپوری میں خود وہاں پر گیا ہوں اور جاکر میں نے اپنی آنکھ سے اُن لوگوں کو دیکھا ہے۔ وہاں بنگالی بولنے والے کوئی ۴۰۔ ۳۵ ہزار لوگ رہتے ہیں اور ۹۹ پرسنٹ نہیں کہوں گا لیکن ۹۵ پرسنٹ مسلمان ہیں۔ وہاں ایک دن صبح کو اخبار میں خبر آئی کہ بنگلہ دیشی ہیں یہ لوگ۔ اور ان کو بارڈر پر چھوڑا جائے گا۔ ۱۵۰ آدمیوں کو ٹرین میں بھر کر کے اور سارے اخباروں میں اس کی فرنٹ پیج پر تصویر بھی چھپی ہے۔ ٹرین میں لوڈ کر کے ان کو بنگال باوجود وہ ہندوستانی سیکھتے ہیں۔ اُن کی کئی نسلیں وہاں گزر چکی ہیں اور بے پناہ پیسے والے ہیں اور بہت زیادہ انویسٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن سوال وہی ہے کہ اگر ان کو ڈیول سیٹیزن شپ دی جائے۔ دوسرے میں یہ سٹیزن شپ کے سوال کو اٹھایا گیا ایک تو میں وزیر داخلہ صاحب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ۱۹۸۳ء میں بہار کے کچھ علاقوں میں کشن گنج۔ پورنیہ۔ اور کٹہیار وغیرہ میں سٹیزن شپ کے نام پر اور بغیر کچھ چیک کئے بنگلہ دیشیوں کا ایک سوال اٹھایا گیا تھا۔ کافی لوگوں کو اس میں پکڑا گیا اور کوشش کی گئی کہ وہاں بھیجا جائے گا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں بھی اس وفد میں شامل تھا۔ اس میں طارق انور صاحب جو کانگریس کے ایکس ایم۔ پی۔ تھے۔ اور جمیل الرحمان صاحب تھے۔ ہم لوگ جاکر مسز گاندھی سے ملے تھے اور ہم نے اُن کو بتایا تھا کہ اس طرح زیادتی ہو رہی ہے۔ گاؤں اور دیہاتوں کے اندر غریب لوگ جو بالکل کچھ جانتے ہی نہیں ہیں اُن سے

بنگلہ دیشی ہو۔ وہ رات میں جاتے تھے کسی بھی جھونپڑی سے لڑکی کو اٹھا لیا اور اس کو لے جاکر دوسرے کمرے میں ریپ کیا۔ اس میں ایک عورت ایسی تھی کہ اس کی بیٹی کو اور اس عورت کو دونوں کو ایک ساتھ ریپ کیا۔ اُن کے نام اور اُن کی عمر میں نے شائع کی ہیں۔ جب یہ لوگ اٹھائے گئے وہاں سے تو کس طرح سے اٹھائے گئے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ باپ کو اٹھا لیا اس کی لڑکیوں اور بچوں کو چھوڑ دیا۔ اسی طرح فیملی سے دوسرے لوگوں کو اٹھا لیا بغیر کوئی پروف دیئے۔

سنسدیہ کاریہ منتر الیہ میں راجیہ منتری اور گرہ منتر الیہ میں راجیہ منتری (شری ایم۔ ایم۔ جیکب) سیٹزن شپ پر بولئے۔

شری محمد افضل: محترم افضل: میں سٹیزن شپ پر ہی بول رہا ہوں صاحب۔ یہ مسئلہ بہت ہی اہم ہے۔ آپ انسانیت کے ناطے سنئے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر سرکار کسی کو اٹھاتی ہے تو اس کو یہ ثابت کرنا چاہیئے کہ تم یہاں کے سٹیزن نہیں

کے بارڈر پر لے جایا گیا۔ پھر بنگال کے اخباروں میں اس کی تصویریں چھپی کہ بارڈر پر بٹھا کر ان لوگوں کے سر مونڈے گئے۔ سر صاف کئے گئے۔ اور اس کے بعد اُن کو دھکیلنے کا کام کیا گیا۔ دھکیلے جانے کے بعد بنگلہ دیش کی جو فورس ہے وہ گولی چلاتی ہے۔ اس میں کچھ لوگ مارے بھی جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو پھر واپس بھیج دیتا ہے اور گھوم پھر کر وہ لوگ پھر واپس آجاتے ہیں وہاں جو ڈیڑھ سو لوگ بھیجے گئے تھے اُن میں سے کچھ واپس بھی آگئے پھر اُس کے بعد راتوں میں وہاں تقریباً ایک دو ہفتہ تک باقاعدہ جو ہماری جمنا پار کی پولیس ہے وہ روز وہاں پر جاتی تھی۔

محترم وائس چیرمین صاحب۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے خود جاکر عورتوں کے انٹرویو لئے ہیں اور میرا جو اخبار نکلتا ہے میں نے اُس کے اندر اس کو شائع کیا ہے۔ لڑکیوں کو ریپ کیا گیا اور رات میں جاکر اُن کو حراس کیا گیا کہ یہاں سے بھاگ جاؤ کیونکہ تم لوگ

کے نام پر اور سٹیزن شپ کا ثبوت مانگنے کے نام پر غریب لوگوں کے ساتھ ظلم اور خاص طور پر ایک کمیونٹی کو نشانہ بنایا جائے یہ بہت ہی ناانصافی کی بات ہے۔

وزیر داخلہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ دہلی میں سیماپوری میں جو ہو تا رہا ہے اس کی تحقیق کریں اور یہ معلوم کریں کہ کیا ان کو یہ ثابت کرنے بھیجا گیا ہے یہ لوگ بنگلہ دیشی ہیں۔ کیا انکی سٹیزن شپ کے بارے میں معلوم کیا گیا تھا۔ پچھلے پندرہ سال سے تین الیکشن میں وہ ووٹ دے چکے ہیں۔ اُن کے پاس راشن کارڈس ہیں اور سب کچھ ہے۔ اس کے باوجود یہ ظلم ہو رہا ہے۔ جب وہاں جاکر احتجاج کیا تب پولیس نے تھوڑی بہت نرمی برتی ورنہ روز وہاں جاکر لڑکیوں کو ریپ کرنے سے لے کر دنیا کا ہر کام وہاں پر کیا۔ اُن کو ہراس کیا۔

انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ جو بل لائے ہیں وہ بل بہت ہی اچھا ہے۔ بہت ہی انسانی بنیاد پر تیار کیا گیا ہے لیکن آپ کی انسانی ہمدردی تمام لوگوں کیلئے ہونی چاہئے کسی مخصوص تعلق سے نہیں ہونی چاہیئے۔ اور سٹیزن شپ کے جو تمام معاملات ہیں اُن پر پوری طرح سے غور کر کے سرکار کو یہ دیکھنا چاہیئے کہ کہاں کہاں پر ناانصافی ہو رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔

ہو۔ دوسرے ابھی ایک بیان آیا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پانچ لاکھ بنگلہ دیشی ہندوستان میں آگئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ سات لاکھ بنگلہ دیشی ہندوستان کے اندر آگئے ہیں میرا کہنا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ غربت اور لاچاری سے تنگ آکر بہت سے بنگلہ دیشی آگئے ہوں۔ اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ وہ بہت سی جگہوں پر وہ موجود ہوں۔ تو سرکار کو اس سلسلہ میں پوری توجہ کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کہاں کہاں بنگلہ دیشی ہیں یہ معلوم کرنا چاہیئے۔ اور اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ ریلوں اور بسوں میں لوگوں کو بھریں اور بارڈر پر دھکیل دیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بنگلہ دیش کی سرکار سے بات کیجیئے جس طرح بہاریوں کے مسئلہ پر پاکستان سے بنگلہ دیش کی بات چل رہی ہے۔ اسی طرح سے آپ بنگلہ دیش سے بات کریں اور اُن کی سٹیزن شپ کے مسئلہ کو طے کریں کہ وہ یہاں کے ہیں یا وہاں کے ہیں۔ اگر وہاں کے ہیں تو آپ اُن کو وہاں بھیج دیجیئے لیکن بنگلہ دیشی

SHRI M. M. JACOB : Mr. Vice-Chairman, Sir, I am thankful to the Members from all parts of the House for giving their unstinted cooperation and support to adopt this Bill at this stage. I am thankful to the hon. speakers, Shrimati Sarla Maheswari, Shri V. Narayanasamy, Shri Dave, Shri Moolchand Meena, Shri Bhandari, Shri Thulsi Reddy, Shri Jagmohan, Shri Ajit Jogi, Shri Fernandes and Shri Afzal who spoke last.

Actually some of the points mentioned by the hon. Members are not directly pertaining to the Bill which is before the House. But at the same time I have taken note of some of the points mentioned for future use, whenever an occasion comes and whenever a necessity arises.

Some of the valid points raised by the hon. Members. One is their asking why there was a delay like this though the U.N. Convention was in 1980 and India was the Chairman of the Working Group. They asked why we delayed it so much, for twelve years. Actually, in 1990, it was introduced in Parliament but because the Lok Sabha was dissolved, it could not come through. That is why some more time has passed. But many countries in the world are yet to adopt it. Some 80 to 90 countries have not been able to adopt this early because of various factors existing in various countries. Probably, the pressure for this kind of an amendment must have been felt in some countries, like India, later on where because of education of women, women going abroad and also getting married to foreigners are noticed more and more. At a time when things are so, it is actually very necessary for keeping up the prestige and honour of Indian women as equal to men abroad, in the international scenario. That is why this Bill is brought and I am happy that all the Members supported it.

Another pertinent question was asked. The time for registration in a foreign mission is given as one year. If it is not possible to be registered during the course of one year, what will happen ? Well, the permission is for a foreign mission to get it registered during the course of one year. But it does bar the power of the Government of India. They can actually refer the matter to the Government of India and the Government of India can exercise its jurisdiction and consider a belated application also.

Another question raised during the course of the debate is, why is this not given retrospective effect ? Sir, as many of the non Members mentioned, it is not intentional or deliberate that retrospective effect should not be given to this. But practically, there are a large number of cases decided and determined earlier after prolonged negotiations, arguments and all that. Once you open up from 1950 to this date, 42 years, it will become an enormous exercise and perhaps, even after bringing this Bill at this time, it may be delayed on account of that. So we thought 'earlier the better' and introduced the Bill in the hope that this would prospectively apply. It may not be very necessary to go retrospectively because the implication of going retrospectively may be large, from 1950 onwards.

Yet another point raised here is about French citizens living in Pondicherry. There are, perhaps, also Portughese citizens living in Goa and French citizens living in Mahe. Not only in Pondicherry, but in the Mahe territory also. There is a liberal policy of grant of long-term facilities for stay of these citizens to any length of time and the Union Territories are given powers to give extension of their stay as long as they want. It was never felt as an absolute necessity of a pressing nature. Perhaps, they may also like to go abroad and stay for some more time there because some of their children may be there as during the time of their job in foreign countries like France, they might have got their employment and citizenship. So we thought it would be a liberal thing to allow them also to stay here as long as they want and go whenever they want and come back whenever they want. It is a liberal thing. It was not intentional. (*Interruptions*).

SHRI V. NARAYANASAMY : I received a reply from the hon. Minister that in principle they agreed. (*Interruptions*).

SHRI M. M. JACOB : I am coming to dual citizenship now. It is actually not in consonance with the provisions of the Indian Constitution. If you want to consider dual citizenship, you have to have

a strenuous job of examining all aspects, including the amendment of the constitutional provisions of the citizenship of India. The main reason perhaps, as I see, is that there is, after the liberalisation of the Visa system, after allowing the NRIs to come into India and have the economic activities freely, the original demand of dual citizenship might not be a pressing need at this time. So I think the difficulties raised by the Indians who have acquired foreign citizenship and who are living abroad at a particular point of time, their demand to come to India for various reasons, those reasons are all met now and instead of six months, Visa is extended to five years. Also the liberal economic policy has helped the investment pattern. So all these things have given a new look to the whole scenario. I am not closing the chapter but I am only explaining the problems arising out of it. (*Interruptions*). Anyway, other countries did not have even the liberalised Visa scheme at that time.

Regarding some other points raised by Mr. Jagmohan about Kashmir, it does not pertain to the Bill now. It is a matter within our country and I do not want to take your time at this point of time. Although I have noted it I do not want to dilate on that aspect now in this House.

I think, I have covered all the major points.

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM (Uttar Pradesh) : The only point left is to get it passed.

SHRI M. M. JACOB : One point you asked about is the illegal migrants coming from Bangladesh and their citizenship. That was also raised here. Regarding that, we have the policy and 25th March 1971 is considered the cut-off date so that any person coming from East Pakistan to India before that date was accepted here. But after that, we enforced very strict rules and law so that illegal immigrants are identified and persuaded to go out or are pushed outside. And you have also mentioned about some illegal migrants being pushed out recently. So determining who are illegal migrants and pushing them out was also a process of law. It does not complicate the matters as far as this Bill is concerned.

I once again thank all the Members for giving the fullest cooperation to get this Bill passed at this time. I thank this House that it took such a short time to discuss this Bill and I commend the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. HANUMANTHAPPA) : The question

> "That the Bill further to amend the Citizenship Act, 1955, as passed by Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA) : We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI M. M. JACOB : Sir, I move :

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

MESSAGE FROM THE LOK SABHA

The Advocates (Amendment) Bill, 1992

SECRETARY-GENERAL : Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha :—

> "In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Advocates (Amendment) Bill 1992 as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 30th November, 1992."

Sir, I lay the Bill on the Table.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA) : The House stands adjourned till 11.00 A.M. on Tuesday.

> The House then adjourned at six of the clock till eleven of the clock on Tuesday, the 1st December, 1992.

MGIPF—406 RSS/93—10-11-93—400.